SHRI ARUN SHOURIE: Sir, a large number of consultancy companies have now come up. At the moment the Engineers India is a very good company. It is providing, the hon. Member has rightly said consultancy services to the petroleum sector. It is also diversifying into other types of consultancy services for turn-key projects. Sir you will be glad to know that among the bidders, who have been qualified for the engineers India Ltd. I generally do not disclose the names but just to satisfy the hon. Member— are ONGC, BHEL, GAIL Larsen and Tubro and some other Sun group. So the public sector enterprises will be making a bid in this regard and naturally they will compete against others.

**Food security project**

*324. SHRI EKANATH K.THAKUR:Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Canadian International Development Agency (CIDA) is providing C$5 million (Rs. 15.5 crore) assistance to implement a food security project in India; and

(b) the details thereof?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD YADAV): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

***Statement***

(a) and (b) As per the available information, the Canadian International Development Agency (CIDA), the official development assistance agency of the Government of Canada is providing assistance of about Rs. 15 crores to Canada's McGill University to work with the Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore, the University of Agricultural Sciences, Dharwad and the University of Agricultural Sciences, Bangalore for a project entitled *'Consolidation of Food Security in South India"*.

The objective of the project is to contribute to the development of long term excellence in Agricultural Universities in South India in the field of post harvest technologies, including food processing.There is no direct involvement of the Government of India in this behalf.

SHRI EKANATH K.THAKUR: Sir, this is a project—the Food Security Project—of far-reaching implications and the newspaper reports, which have appeared, say that storage and food preservation technologies will be improved with this project and they will be commercialised on an all-India basis. But, the Minister has gone on to say that there is no direct involvement of the Government of India in this regard and I am surprised with his Statement. I would like to ask the Minister what is exactly the Food Security Policy of the Government of India *vis-a-vis* a common man and does it Conclude Zero Tolerance Level of starvation deaths as one of the ingredients of the policy?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री सुभाष महरिया): महोदय, CIDA कंपनी केनेडियन गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जो मैकगिल यूनिवर्सिटी के जरिए हमारे देश की तीन यूनिवर्सिटीज़ के साथ, जो फसल हम मार्किट में लेकर आते हैं, उस फसल को काटने के बाद लासिज़ को किस तरह से रोका जा सकता है, इस पर कार्य कर रही है। इसके लिए मैकगिल यूनिवर्सिटी ने हमारे यहां की तमिलनाडु कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर,कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ तथा कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर के साथ .....

**श्री एकनाथ के ठाकुर**: सर, यह इनफॉमेंशन तो दी हुई है। मुझे यह पूछना है कि ...

**श्री सभापति** : उन्हें बोलने दीजिए।

**श्री सुभाष महरिया** : इनके साथ मिलकर फूड सिक्योरिटी के लिए फूड लासिज़ को कैसे बचाया जा सकता है, इसके लिए साढ़े 15 करोड़ रूपये लगाने की एक योजना बनाई है। कृषि मंत्रालय के जरिए जो सूचना आयी है, उसके तहत यह कार्यवाही अभी प्रोसैस में है। माननीय सदस्य ने पूछा है कि आप लोग किस प्रकार से फूड सिक्योरिटी के लिए फूड लासिज़ को बचाने का काम कर रहे हैं । इंडियन ग्रेन स्टोरज मेनेजमेंट ऐंड रिसर्च इंस्टीटयूट जो है, उसके तहत 4.75 परसेंट लॉसिज़ जो हमारे अभी है, जो फसल काटने, धुलाई,भंडारण, कीड़े-मकोड़े, पक्षी,चूहों के कारण हो रहे हैं, उसके लिए 1998-99 में wheat के ऊपर जो रिपोर्ट आयी, हमारे लिए खुशी की बात है कि जो स्टोरेज लॉसिज़ है, वे सन् 1998-99 के बाद 0.34 परसेंट थे, और अभी हाल ही में.....

SHRI EKANATH K. THAKUR: Sir, my question is whether Zero Tolerance Level for starvation deaths is an element of their policy.

**श्री सुभाष महरिया** : 0.36 परसेंट रहे । जो ज़ीरो टॉलरेंस की बात है, इसके लिए कैनेडियन सरकार की मैकगिल कम्पनी ने जो रिसर्च करने का काम शुरू किया है, उसके ऊपर देखरेख जारी है। अभी 30 जनवरी को ही उसके बारे में आई0सी0ई0आर0 को रिपोर्ट मिली है, वह उसके ऊपर मनन

कर रही है, अध्ययन कर रही है। उस पर आगे किस प्रकार से कार्यवाही हो सकती है, उसका मसविदा तैयार किया जा रहा है।

SHRI EKANATH K. THAKUR: Sir, the answer has not come. My question was whether Zero Tolerance Level for starvation deaths is one of the elements of the Food Security Policy of this Government. My second supplementary—let him answer both the questions together—is whether Government of India is doing anything to investigate the widespread reports of starvation deaths in India. Sir, whenever a starvation death is reported, the State Governments get into action with all alacrity, speed and all the force at their command to cover it up. And, they try to ensure that every report is hushed up, as if there is no starvation death in this country. Does the Government have a proposal to set up a Central Agency to look into every single starvation death? Sir, starvation death is a stigma on the polity and democracy of this country. After nine Five Year Plans, there have been starvation deaths in this country and Food Minister of the Government of India must assure this House that there would be no starvation deaths. If there is any starvation death, Government of India will not allow the State Government to cover it up and examine every starvation death through the agency of CBI.

MR. CHAIRMAN: That is enough.

**श्री शरद यादव** : माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा, उसमें अभी एक और विस्तार उन्होंने कर दिया है, वह अच्छा किया है । मैं उसके बारे में आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं कि पिछली बार आपने कहा था, इस बाबत हमने अपने मंत्रालय में टास्क फोर्स बनाया है। उसमें हम रूरल डैवलपमेंट और ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोगों को भी शरीक कर रहे हैं और आपके माध्यम से मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से तीन-चार महीने पहले यह सवाल बहुत गंभीर और बहुत खराब था, इसके संबंध में सूबाई सरकारों के साथ बात करके, अपने मंत्रालय में एक सेल बनाकर, एक टास्क फोर्स बनाकर हम इसके पीछे लगे हुए हैं। मैं यह मानता हूं कि निश्चित रूप से हम पूरी तरह से इसमें सफल नहीं है लेकिन इस मामले में जो हमारी कूवत और क्षमता है, उसके अनुसार इस सवाल को हल करने में हम लगे हुए हैं ।

**श्री दत्ता मेघे**: सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह तो 15 करोड़ की प्रौद्योगिक एजेंसी है। इससे पूरे देश का काम होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। आज भी पूरे देश में राज्यों के अनाज-भंडारों में बहुत बड़े पैमाने पर अनाज सड़ रहा है और खराब हो रहा है। आप किसी भी गोदाम में जाएंगे तो पाएंगे कि एक तरफ तो लोगों को खाने के लिए भी अनाज नहीं मिलता है .....

**श्री सभापति** : आप क्वेश्चन कीजिए।

**श्री दत्ता मेघे** : इसलिए सर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि भंडारों में जो खराब अनाज है, उसे निकाल कर जहां भी स्टार्वेशन हो रहा है, भूखमरी है, खासतौर से जो आदिवासी एरियाज़ है, जहां अनाज नहीं मिलता है और लोग मर रहे हैं-इस दृष्टि से कि वहां कम से कम भुखमरी हो, इसके लिए सरकार कोई इमीडिएट कार्यवाही करने वाली है या नहीं ?

**श्री शरद यादव** : सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, वह इस सवाल से नहीं उठती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अनाज सड़ रहा है, लगातार इस तरह का प्रचार करना ठीक नहीं है। अनाज सड़ता है... ( **व्यवधान** ) ... सुनिए मेरी बात को। ... (**व्यवधान** ) ...

**श्री सभापति** : अब उन्हें बोलने दीजिए, ऐसी क्या बात है? ... ( **व्यवधान** ) ... बोलने दीजिए, यह अच्छा नहीं है।

**श्री शरद यादव**: सभापति जी, मैं निवेदन कर रहा हूं कि एफ0सी0आई0 के पास जो स्टोरेज है, वह बहुत ज्यादा नहीं है। माननीय सदस्य तो महाराष्ट्र के हैं- उनकी सरकार के हाथ में ज्यादा फूड ग्रेन्स है फूडग्रेन्स की कोई कमी नहीं है। आपके यहां सब जगह हमने फूडग्रेन पहुंचाया हुआ है, रखा हुआ है। सड़ान की या ऐसी कोई खबर जब आती है, इस दौर में जो अनाज के सड़न की खबरें आ रही हैं, उसमें स्टेट गवर्नमेंट के वेयर हाउसेस जो है, उनमें दिक्कतें आ रही हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जो सड़ा हुआ फूडग्रेन होगा,भारत सरकार उसको नहीं देगी। एफ0सी0आई0 उसको नहीं लगी। हम अच्छा और ठीक फूउग्रेन ही भारत के लोगों को देंगे। जहां तक भुखमरी का सवाल है, आप पक्की तरह से हमें बताइए कि यहां-यहां भुखमरी हो रही है, हम तत्काल वहां टास्क फोर्स पहुंचाएंगे, तत्काल जो भी संभव होगा, वह करेंगे लेकिन आप अपनी सरकारों से भी कहिए कि वे भी उतनी ही मुस्तैद रहें जिस तरह से हम मुस्तैद रहने के लिए कहते हैं। ...(**व्यवधान** ) ....

**श्रीमती सरला माहेश्वरी** : सर, एफ0सी0आई0 के गोदाम में 75 लाख टन अनाज की चोरी हो गई, उस घोटाले का क्या हुआ, मंत्री जी कम से कम वह तो बताएं।

**श्री सभापति** : वह अलग क्वेशचन है। अभी कीड़े-मकोड़े के खाने तक का इलाज इन्होंने किया है ... ( **व्यवधान** ) ... चोरी का अलग क्वेश्चन है *(Interruptions)* No, I won't allow —*(Interruptions)* आप बैठिए... बैठिए....( **व्यवधान** )....इसको अगले सेशन में करेंगे।

SHRI M.V. RAJASEKHARAN: Mr. Chairman, Sir, if there is food security today in our country, it is because of the great vision of our former Prime Minister, Pt. Nehru, He, in the beginning, set up a number of agricultural universities in this country in collaboration with the United States and other countries, particularly, on the model of Land Grant colleges, with the result that by Green Revolution, we have been able to achieve a degree of food security in this country, which also gave the political stability. Now, what I would like to know from the hon. Minister in this. As he himself admitted, millions of tonnes of foodgrains are being wasted, during the harvesting season as well as during the post-harvest season, in various godowns in the country...

MR. CHAIRMAN: You put your supplementary.

SHRI M.V. RAJASEKHARAN: Therefore, I would like to know form the hon. Minister as to whether the Government of India will play a proactive role to involve various agencies for bringing in new technology, that too, as quickly as possible, so that the foodgrains that are being wasted are saved and the food security is extended. Sir, why I am saying this is...

MR. CHAIRMAN: Let the Minister reply now...

SHRI M.V. RAJASEKHARAN: I wish to put my second supplementary.

MR. CHAIRMAN: No; second supplementary is not allowed.

**श्री शरद यादव** : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है वह इससे संबंधित नही है । इन्होंने पूछा है कैनेडियन गवर्नमेंट से मदद आ रही है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो फूड सिक्योरिटी का मामला है वह देशभर का मामला है। अभिजीत कमेटी की रिपोर्ट हमारे पास आई हुई है। हम इसमें अपनी तरह से सिलसिलेवार लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि भारत सरकार कितनी गंभीर है। फूड सिक्योंरिटी के लिए जो हमारी जिम्मेदारी है, उसमें हमने क्या किया है। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं। 1999-2000 में फूड सिक्योरिटी दी जाती थी 9200 करोड़ सब्सिडी से इसका रिश्ता है। 2000-2001 में 12000 करोड़, 2001-2002 में 17494 करोड़। इस साल हमारी सब्सिडी फूड पर है, फूडग्रेन वैलफेयर पर सब्सिडी है। हमारे अकेले मंत्रालय 27750 करोड़ है। यानी हिन्दुस्तान के भोजन की जो सुरक्षा है, उस पर भारत सरकार के हाथ में जो

ताकत है। उसके अनुसार हमने यह एलॉटमेंट तिगुना बढ़ाया है। मैं यह निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं।

**श्री प्रफुल्ल पटेल** : क्या हम 15-15 करोड़ की मदद विदेशों से लेना बन्द करेंगे? आप 15 करोड़ की मदद कनेडियन गवर्नमेंट से ले रहे हैं। हमारा देश इतना बड़ा है, क्या हम लोगों के पास क्या 15 करोड़ नहीं है? वह टैक्नॉलाजी लेने के लिए, मदद ले रहे है? क्या हम लोग हमेशा देश को और दुनिया को यही पिक्चर देंगे कि हमें 15-15 करोड़ की मदद चाहिए, विदेशों से? कहीं इसके लिए भी कोई विचार किया जाएगा? यह बड़ा सवाल है, महोदय, मैं यह नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन यह 15-15 करोड़ की मदद, इतने बड़े देश में, विदेशों से टैक्नॉलोजी के लिए देना, यह कोई बहुत उचित बात नहीं है। इसके बारे में भी कभी सदन में गंभीरता से विचार करना चाहिए ... ( **व्यवधान** ) ...

SHRI K. NATWAR SINGH: I agree with the piont raised by Shri Praful Patel. *(Interruptions)* You should not have taken Rs. 15 crores. It is a disgrace for our country. Why have you taken Rs.15 crores? *{Interruptions)*

**श्री सभापति** : आप बैठिए। इनको बोलने तो दीजिए। ... ( **व्यवधान** ) ...

**श्री शरद यादव** : सभापति महोदय, प्रफुल्ल पटेल जी ने जो बात कही है,इसको मैं थोड़ा सा साफ कर दूं। कनेडियन यूनिवर्सिटी में हमारे यहां के प्रोफेसर राघवन काम करते हैं उनके व्यक्तिगत प्रयास से उन्होंने तीन यूनिवर्सिटीज में विजिट किया था और उन्होंने साऊथ इंडिया की तीन यूनिवर्सिटीज के लिए एमओयू साईन किए और इससे मदद का उन्होंने ऐलान किया। वह प्रोसेस होकर एग्रिक्लचर मिनिस्ट्री में आई । हमने कभी मांग नहीं की है। ... ( **व्यवधान** ) .....

**श्री सभापति** :श्री बसु बैठ जाइए ।

**श्री शरद यादव** : महोदय, भारत सरकार अपनी योजनाओं पर अपने तरीके से खर्च कर रही है । जिस सवाल से मेरा वास्ता नहीं था, ... ( **व्यवधान** ) .... मेरी सुनिए। इस सवाल से हमारा कोई वास्ता नहीं था। सवाल पूछा है, उसकी जानकारी सदन को देनी है इसलिए मैंने बताया है।

**श्री सभापति** : ठीक है, आपने दे दी, अच्छा किया। श्री नीलोत्पल बसु।

**श्री नीलोत्पल बसु**: सर, मंत्री जी ने बढ़ती हुई सब्सिडी का आकलन किया है और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम खाद्यान्न सुरक्षा के प्रति सचेत है। सर, अगर देखा जाए कि पिछले तीन चार साल में हमारे भंडार कैसे बढ़े है, तब पता चलेगा कि इसका मूल कारण क्या है । 2001-2002 का जो बजट था, उसमें जो फूड प्राइसेस बढ़ी थी, व्हीट में 64 परसेंट और राइस में 46 परसेंट वहां से हमारे खाद्यान्न भंडार भरने शुरू हुए हैं । जैसे-जैसे हमारे खाद्यान्न के भंडार भरते

गए, उसके लिए प्रोक्योरमेंट का खर्चा, फूड सब्सिडी में दिखाया जाएगा, ट्रांसपोटेंशन का खर्चा सब्सिडी में दिखाया जाएगा, इसका मतलब यह हुआ, because of the price rise in the PDS for wheat and rice, the food subsidy has gone up. So, it is counterproductive. You are increasing the subsidy and, at the same time, increasing the price at a level, which is beyond the purchasing power of the people. You are, on the one hand, increasing the food subsidy and, at the same time, creating a situation, whereby people do not have access to the food for which you are giving the subsidy. So, my question is this. Will the Government of India think of liquidating this huge stock by launching a massive Food for Work Programme whereby our fod subsidy is also brought down and, at the same time, we have a major employment generation? गए, उसके लिए प्रोक्योरमेंट का खर्चा, फूड सब्सिडी में दिखाया जाएगा, ट्रांसपोटेंशन का खर्चा सब्सिडी में दिखाया जाएगा, इसका मतलब यह हुआ,

**श्री सुभाष महरिया** : सभापति जी, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि एस0जी0आर0वाई0के तहत, अंत्योदय **योजना** के तहत मात्र दो रूपये किलो गेहूं और तीन रूपये किलो चावल दिया जा रहा है। बी.पी.एल. के तहत लोगों को चार रूपये पंद्रह पैसे किलो गेहूं और पांच रूपये पैसठ पैसे किलो चावल दिया जा रहा है। यह बी0पी0एल0 में दिया जा रहा है। आपने जानना चाहा है कि हमारे यहां जो छत्तीस करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं उन्हें मरने नहीं दिया जाए। सबके यहां अनाज पहुंचे, इसके लिए अभी हाल ही में पचास लाख टन का अतिरिक्त आवंटन भी किया गया है। पचास लाख फैमिलीज यानी तीन करोड़ लोगों को सीधा-सीधा लाभ पहुंचाया गया है .... ( **व्यवधान** )...

**श्री नीलोत्पल बसु**: मेरा प्वाइंट यह नहीं है। मेरा प्वाइंट यह है कि अगर हमारे यहां लोगों को जरूरत है फिर भी हमारा भंडार क्यों बढ़ता जा रहा है? हमारा फूड प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, पर कैपिटा फूड अवेलिबिलिटी कम होती जा रही है लेकिन भंडार कम नहीं हो रहे है .... ( **व्यवधान** ) ... उसके लिए खर्च हो रहा है ... ( **व्यवधान** ) ...

**श्री सुभाष महरिया** : सभापति जी, यह तो हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे देश में प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है .... ( **व्यवधान** ) ....

SHRI NILOTPAL BASU: Food Production, the production is going down. इकोनॉमिक सर्वे देख लीजिए I What he is saying is incorrect. *(Interruptions)* He is misleading the House. इकोनॉमिक सर्वे बताता है प्रोडक्शन कम हो रहा है।

**श्री सुभाष महरिया** : सभापति महोदय,.... ( **व्यवधान** ) .... की स्थिति में पहुंचे.... ( **व्यवधान** ) ....

**श्री सभापति** : बोलने दीजिए........( **व्यवधान** ) ......

**श्री नीलोत्पल बसुः** ड्राउट की वजह से ..... ( **व्यवधान** ) ....

**श्रीमती सरला माहेश्वरीः** सभापति महोदय, अनाज का भंडार इतना भरा हुआ है कि .... ( **व्यवधान** ) ... कहीं भी पहुंचा सकते हैं ... ( **व्यवधान** ) ...

**श्री सभापति :** बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, यह क्या कर रही है आप ... ( **व्यवधान** ) ... आप बोलने तो दो.... ( **व्यवधान** ) .....

**श्री शरद यादव :** सभापति महोदय, ये जो इतने बड़े-बड़े सवाल पूछ रहे हैं, ये इसमें से उठते ही नहीं है। फिर भी मैं क्योंकि माननीय सदस्य ... ( **व्यवधान** ) ...

**डा.अबरार अहमद :** सवाल उठते है। बेसिक सवाल है।

**श्री सभापति :** आप बैठिए, बोलने तो दो.... ( **व्यवधान** ) ...

**डा. अबरार अहमद** : आप यह बताइए की क्या कृषि उत्पादन बढ़ा है? यह बात सदन के अंदर कहना .... ( **व्यवधान** ) ... कृषि उत्पादन बढ़ा है ... ( **व्यवधान** ) .... आप बताइए ..... ( **व्यवधान** ) ......

**श्री सभापति :** आप गुस्से में आ रहे हैं। जवाब देने नहीं दे रहे है। .... ( **व्यवधान** ) ....

**श्री मनोज भट्टाचार्य :** जो .सवाल पूछा है वे बताएं .... ( **व्यवधान** ) ...

**श्री सभापति :** आप नहीं मान रहे तो ये कैसे मानेंगे ... ( **व्यवधान** ) ...

**श्री शरद यादव :** सभापति जी, हमारे यहां अन्न का जो भी उत्पादन बढ़ा या घटा है उसकी पक्की जानकारी, पक्के आंकड़े मेरे पास नहीं है .... ( **व्यवधान** ) .....

**श्री नीलोत्पल बसुः** आपका इकोनॉमिक सर्वे हुआ है।

**श्री सभापति** : यह इनका विषय नहीं है कि प्रोडक्शन कितना है ..... ( **व्यवधान** ) ...

**श्री नीलोत्पल बसु**: दो हफ्ते पहले इकोनॉमिक सर्वे हुआ है। उनके पास पक्की जानकारी नहीं है... ( **व्यवधान** ) ....

**श्री सभापति** : वह ठीक है ।

**श्री नीलात्पल बसु**: जानकारी नहीं है तो आप ....( **व्यवधान** ) .... बंद कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन ऑवर का .... (व्यवधान ) ....

**श्री सभापति :** ठीक है, आप बोलने तो दीजिए।

**श्री शरद यादव** : सभापति जी, ये मेरी बात नहीं सुन रहे हैं ..... ( **व्यवधान** ) .....

**डा0 अबरार अहमद** : इन्हें जानकारी नहीं है ... ( **व्यवधान** )...

**श्री सभापति** : ये बोल रहे हैं, आप मत बोलिए।

**श्री शरद यादव** : सभापति जी, मैं जो कहना चाहता हूं उसे ये सुनना नहीं चाहते है।मैं उनकी उस बात का जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूं जो कि सवाल में ही नहीं है। असल में उन्होंने पूछा है कि फूड ग्रेन बढ़ रहा है या कम हो रहा है। सवाल यह नहीं है, उन्होंने एक बात यह कही है कि ... ( **व्यवधान** )

**श्री सभापति :** मंत्री महोदय, सवाल यह है कि देश में फूड स्टॉक बहुत है फिर भी लोगों में भूख की शिकायत है। इसका समाधान किस प्रकार से होगा ? This is the question. आज आप इसका जवाब नहीं दे सकते ... ( **व्यवधान** ) ...

**श्री शरद यादवः** नहीं मैं जवाब दे रहा हूं... ( **व्यवधान** ) ...

**श्रीमती सरोज दुबे**: सभापति महोदय, यह ... ( व्यववधान )...

**SHRI DINESH TRIVEDI: Sir, there should be a Half-an-Hour Discussion on this issue! *(Interruptions)***

**श्री सभापति** : आप एक मिनट बैठिए। मैं ऐसा समझता हूं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। आधे घंटे की चर्चा हाउस में ... ( **व्यवधान** ) ... एक मिनट ठहरिए ... ( **व्यवधान** ) ...

**श्री शरद यादव** : सभापति महोदय, आप हमें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं तो क्या होगा?

**श्री सभापति** : मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा लेकिन माननीय सदस्यों की फीलिंग यह है कि स्टॉक होते हुए भी भूख की समस्या क्यों पैदा हो रही है। इसका कारण लोगों को चाहिए ... ( **व्यवधान** ) ...

**श्री शरद यादव** : सभापति जी, मैंने इसके कारण को विस्तार से पहले बताया था। आप तो इसके मामले बहुत गहराई से जानते है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह सवाल पूछ रहे हैं ... ( **व्यवधान** ) ...

**श्री सभापति** : आपके पास एग्रीकल्वर डिपार्टमेंट नहीं है... ( **व्यवधान** ) ...

**श्री शरद यादव** : सभापति जी, मेरा इस चीज से वास्ता है कि फूड स्टॉक कितना है। अभी जो फूड स्टॉक की पोजीशन है उसके अनुसार देश भर में बावन लाख मीट्रिक टन अनाज है। चौदह सूबे है? जो ड्राडट प्रोन है, उन को फ्री दिया है। अब अगर उसे स्टेट गवर्नमेंट नीचे नहीं बांट पाती है, नहीं

काम करा पाती है तो इस में भारत सरकार क्या करेगी सभापति महोदय, हम ने तो 30 किलो की जगह 35 किलो किया है।... ( **व्यवधान** ) ...

• 325. [The Questioner (Shri Vijay Singh Yadav) was absent. For answer *vide* page 34 *infra.]*

Mr. Chairman: Question No. 326.

**Boundary Dispute with Myanmar**

*326. SHRI RISHANG KEISHING: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a)whether any boundary dispute exists between Myanmar and India;

(b) if so, what efforts have been made to settle the dispute in a friendly and peaceful way; and

(c) the steps taken to further improve and strengthen the friendly relations between the two countries?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI VINOD KHANNA): (a) to (c) Sir, a Statement is placed on the Table of the House.

***Statement***

*Boundary dispute with Myanmar*

1. Under the boundary agreement of 1967, a Joint Boundary Commission was constituted for demarcating the India-Myanmar boundary. Out of 1643 kms. of the India-Myanmar boundary, demarcation of 1472 kms. has been completed. 136 kms. in the Lohit sub-sector of Arunachal Pradesh and 35 kms. in the Kabaw valley of Manipur sector remains undemarcated. Although the undemarcated sectors are not an issue in bilateral relations, discussions in this regard are held in the institutional mechanisms for boundary-related issues.

2. It was also agreed in the Joint Boundary Commission by the two Governments to maintain all boundary pillars and to move forward with joint inspection, repair and restoration of pillars. The first meeting between the Heads of Survey Deparments of India and Myanmar was held in Yangon in September 1993.